



रथ यात्रा स्तुति मंत्र:नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने। बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः॥

(अर्थ: जो नित्य और परमेश्वर भगवान नीलाचल [पुरी] में निवास करते हैं, उन बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ को मेरा नमन है।

अनाथ रक्षक श्लोक : अनाथस्य जगन्नाथ नाथस्त्वं में न संशयः।यस्य नाथो जगन्नाथस्तस्य दुःखं कथं प्रभो॥

(अर्थ: हे जगन्नाथ! आप अनार्थों के नाथ हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हे प्रभो! जिसके स्वामी स्वयं जगन्नाथ हों, उसे भला दुःख कैसा?)

रथ स्पर्श का श्लोक: रथं स्पृष्ट्वा प्रेम्णा विरलरथयात्रा सुरभितम्। जगन्नाथं नत्वा चरमचिरसौख्यं भवतु मे॥

(अर्थ: भगवान जगन्नाथ के सुगंधित दिव्य रथ का प्रेमपूर्वक स्पर्श करके और उन्हें नमन करके मैं परम और शाश्वत सुख प्राप्त करुं।)

रथयात्रा में भारी भीड़ से भगदड़, 2 की मौत, 5 श्रद्धालु अस्पताल में भर्ती

पुरी ● एंर्जेंसी

ओडिशा के पुरी में गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस घटना में कई श्रद्धालु घायल हो गए। दो श्रद्धालु की मौत की भी खबर है।

यह घटना बड़ा डांडा (ग्रेंड रोड) पर हुई, जहां भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ खींचने के कार्यक्रम को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु जमा हुए थे।

आपातकालीन बचाव दलों ने घायलों को तुरंत बाहर निकाला और पास के अस्पतालों में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस, दमकल विभाग और स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत बचाव और भीड़ को नियंत्रित करने का अभियान शुरू किया, ताकि



की शिकायत करने वाले लगभग 200 मरीजों को अब तक पुरी के अस्पतालों और अस्थायी स्वास्थ्य सुविधाओं में भर्ती कराया गया है।

जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इसमें हर साल देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। भगदड़ के सही कारण की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अधिकारी स्थिति का जायजा ले रहे हैं।

गुरुवार को पवित्र तटीय शहर पुरी में भव्य वार्षिक रथ यात्रा देखने के लिए लाखों लोग एकत्रित हुए। विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत निर्धारित समय से पहले ही दिन में दिव्य भाई-बहनों और अन्य देवी-देवताओं के लिए 'पहंडी बीजे' अनुष्ठान के साथ हुई।

सीएम माझी दुख जताया

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस घटना में हुई मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए।

'पहंडी बीजे' अनुष्ठान के दौरान पवित्र भाई-बहनों और अन्य देवी-देवताओं को 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर से उनके सजाए गए रथों तक भव्य शोभायात्रा के साथ ले जाया गया। इस दौरान घंटा, कहली और तेलिंगी बाजा जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्रों की मधुर और दिव्य ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजती रही।

पेट्रोल सस्ता, फिर भी इथेनॉल पर दांव क्यों? लागत से आगे की है पूरी कहानी

नई दिल्ली ● एंर्जेंसी

अगर सवाल सिर्फ उत्पादन लागत का हो, तो पेट्रोल स्पष्ट रूप से इथेनॉल पर भारी पड़ता है। भारत में रिफाइनरी से निकलने वाले पेट्रोल की बेस उत्पादन लागत 54 से 57 प्रति लीटर के बीच है। रिफाइनिंग, परिवहन और अन्य खर्च जोड़ने के बाद इसकी कुल लागत लगभग 76 से 79 प्रति लीटर तक पहुंचती है।

दूसरी ओर, इथेनॉल की वास्तविक लागत इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर निर्भर करती है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, सरकारी सहायता और अन्य राजकोषीय लागतों को शामिल करने पर चावल आधारित इथेनॉल की अनुमानित लागत 126 प्रति लीटर, मक्का आधारित 95 प्रति लीटर और गन्ने के रस से बनने वाले इथेनॉल की 85.5 प्रति लीटर तक बैठती है। मामला केवल उत्पादन लागत तक सीमित नहीं है। ऊर्जा क्षमता के लिहाज से भी पेट्रोल आगे है। एक लीटर पेट्रोल लगभग 32 मेगाजूल ऊर्जा देता है, जबकि एक लीटर इथेनॉल से करीब 21 मेगाजूल ऊर्जा मिलती है। यानी समान दूरी तय करने के लिए इथेनॉल की अधिक मात्रा की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से ऊर्जा-समृद्धता के आधार पर इथेनॉल की प्रभावी लागत पेट्रोल से कहीं अधिक दिखाई देती है।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यदि इथेनॉल महंगा है और उसकी ऊर्जा क्षमता भी कम है, तो भारत समेत दुनिया के कई देश इसे बढ़ावा क्यों दे रहे हैं?

इसका जवाब अर्थशास्त्र से ज्यादा भू-राजनीति और राष्ट्रीय रणनीति में छिपा है।

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा विदेशों से आयात करता है। पश्चिम एशिया में तनाव, ओपेक देशों के उत्पादन फैसले या वैश्विक संकट के समय तेल की कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं। ऐसे में पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग आयातित तेल पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनती है।

इसके अलावा, दुनिया कार्बन उत्सर्जन घटाने और नेट-जीरो लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इथेनॉल जैसे जैव-ईंधन जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने का

गगनयान मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने ISRO छोड़ा

बेंगलुरु। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) से पिछले 10 महीनों में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों ने या तो इस्तीफा दे दिया है या स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली है। नौकरी छोड़ने वाले वैज्ञानिकों में गगनयान और दूसरे अहम मिशनों से जुड़े वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इसके बाद अंतरिक्ष विभाग ने 14 जुलाई को नया निर्देश जारी किए हैं। नौकरी छोड़ने की प्रक्रिया अब सख्त की जाएगी। इस मामले में केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ISRO में लोग आते-जाते रहते हैं। इस्तीफा देने वालों में वरिष्ठ वैज्ञानिक विक्रम जोसेफ ठी भी शामिल हैं। वे LVM3 प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। यही लॉन्च व्हीकल गगनयान मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा।

किसी हिम्मत नहीं मेरे कार्यकर्ताओं का नुकसान कर दें : नरोत्तम मिश्रा

आशुतोष की छमता नहीं मेरा टिकट काट दें वे कोई और उन तक पहुंचना आपकी छमता नहीं उनसे भी बात करेंगे

दतिया ● एंर्जेंसी

बीजेपी के सीनियर लीडर डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों से कहा, 'किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे कार्यकर्ताओं का नुकसान कर दे। अगर नौबत आई तो मैं भी तुम्हारे साथ जेल जाऊंगा।' पूर्व गृहमंत्री ने ये बात गुरुवार को दतिया में कही। वे बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी उनके साथ थे।

मिश्रा ने कहा, 'लोग कहने लगे कि आशुतोष ने टिकट काट दिया। उसकी क्षमता है टिकट काटने की? टिकट काटने वाले कोई और हैं। वहां हमें बात करनी है, हम करेंगे। उस दिन आप लोगों की आंखों में आंसू देखकर मैं भी भावुक हो गया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा से बदला लेना है। अरे भाई बदला भाजपा से नहीं, कांग्रेस से लेना है। हर हाल में आशुतोष तिवारी को जिताना है।'

कार्यकर्ताओं को दिलाई पीतांबरा माई की शपथ-

नरोत्तम ने कहा कि वे हमेशा अपने चुनाव से ज्यादा दूसरे चुनावों में ताकत लगाते रहे हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं को



आश्वस्त करते हुए बोले कि यदि किसी पर प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो वे उसके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पीतांबरा माई की कसम खिलाकर बीजेपी के पक्ष में मतदान कराने का संकल्प भी दिलाया।

नरोत्तम ने कहा- जो हुआ, भ्रम-क्रोध में आकर हुआ। दतिया के दुकानदार भाइयों ने तीन दिन बाजार बंद रखा, उनका तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं। कार्यकर्ता बंधुओं, मैं तुम्हारे मन को समझ रहा हूं। तुम भी मेरे मन को समझने की कोशिश करो।

होर्मुज में भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक

तेहरान/वाशिंगटन ● एंर्जेंसी

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा जोखिम को देखते हुए भारत ने अगले आदेश तक होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों (सीफेयरर्स) को नई तैनाती पर रोक लगा दी है। यह आदेश जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधन



कंपनियों और नाविकों की भर्ती करने वाली रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस

लाइसेंस (RPSL) कंपनियों पर लागू होगा। सरकार ने सभी समुद्री कंपनियों को अरब की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट और आसपास के समुद्री इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा गया है कि वे नौवहन संबंधी सभी चेतावनियों और सुरक्षा सलाह पर लगातार नजर रखें और इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट

फैसिलिटी सिक्वोरिटी (ISPS) कोड का पुरी तरह पालन करें। सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब इसी हफ्ते होर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास हुए ईरानी हमलों में दो भारतीय नाविकों की मौत हो गई। अमेरिका-ईरान संघर्ष के बाद इस समुद्री मार्ग पर हमलों का खतरा बढ़ गया है।

चार टीमें तलाश में जुटीं, खलघाट में देखे जाने की सूचना

पांच दिन बाद भी पति फरार, 10 हजार का इनाम घोषित

इंदौर ● संवाददाता

इंदौर में डाक विभाग की पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी हत्याकांड में पांच दिन बाद भी मुख्य आरोपी और मृतका के पति अखिलेश सैनी का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस की चार से अधिक टीमें अलग-अलग जगहों पर उसकी तलाश में जुटी हैं। आरोपी की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है।

11 जुलाई को हुई थी हत्या

11 जुलाई को डाककुंज कॉलोनी स्थित सरकारी आवास में 38 वर्षीय पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी की हत्या कर दी गई थी। घटना के समय उनके दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। स्कूल से लौटने पर बच्चों ने घर के अंदर मां का खून से लथपथ शव देखा। वारदात के बाद से उर्मिला का पति अखिलेश सैनी फरार है।

मोबाइल साथ नहीं ले गया आरोपी

जांच अधिकारियों के मुताबिक अखिलेश ने पूरी वारदात पहले से योजना बनाकर की। पुलिस का मानना है कि उसे यह जानकारी थी कि जांच में मोबाइल फोन

सबसे अहम सुराग होता है। इसी वजह से वह अपने दोनों मोबाइल फोन घर पर छोड़कर फरार हुआ, जिससे उसकी लोकेशन और संपर्कों का पता नहीं चल पा रहा है।

नई सिम और डिजिटल लेनदेन के भी नहीं मिले सुराग

पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने फरारी के दौरान नई सिम खरीदी होगी, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है। बैंक खाते, यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों से भी उसकी कोई गतिविधि सामने नहीं आई है। जांच में पता चला है कि आरोपी बच्चों को दोपहिया वाहन की चाबी देने के बाद ऐसे रास्ते से निकला, जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। बाद में उसके फुटेज इंदौर रेलवे स्टेशन पर मिले। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि उसने दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराया था, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया। इसके बाद वह सरक्टो बस स्टैंड क्षेत्र की ओर जाता दिखाई दिया।

पुलिस को कुछ दिन पहले सूचना मिली थी कि अखिलेश सैनी को खलघाट क्षेत्र में देखा गया था। इस सूचना की भी जांच की जा रही है, हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।



कारोबार और रिश्तेदारों पर भी नजर

पुलिस आरोपी के अगरबत्ती कारोबार से जुड़े लोगों की भी जानकारी जुटा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि वह किसी परिचित, कारोबारी या रिश्तेदार के संपर्क में तो नहीं है। भोपाल में रहने वाले उसके माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई है।

ऑंकारेश्वर में हुआ अस्थि विसर्जन



उधर, उर्मिला सैनी की अस्थियों का ऑंकारेश्वर में विसर्जन कर दिया गया है। अब उनके दोनों बच्चे प्रेक्षा और अव्यक्त की शेष शोक रस्में खंडवा स्थित नाना-नानी के घर पर पूरी कराई जाएंगी। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश लगातार जारी है। उसकी गिरफ्तारी या उसके बारे में पुख्ता सूचना देने वाले को 10 हजार रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

संक्षेप

स्टोर मैनेजर ने 10 लाख के जूते-कपड़े बेचकर रकम हड़पी

इंदौर। विजयनगर थाना क्षेत्र में सी-21 मॉल स्थित एक शोरूम के स्टोर मैनेजर पर करीब 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उसने बिना बिल के जूते, कपड़े और अन्य सामान बेचकर ग्राहकों से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कराए। विजयनगर पुलिस के मुताबिक, सुयश विहार कॉलोनी निवासी कंपनी मैनेजर सितलेश यादव की शिकायत पर रोशन कुमार यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। रोशन मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और सी-21 मॉल स्थित एसिक्स (ASICS) शोररूम में स्टोर मैनेजर था। वह जून 2024 में नौकरी पर रखा गया था और 13 सितंबर 2025 को नौकरी छोड़कर चला गया।

बीच-बचाव

करने पर कपड़ा

व्यापारी पर हमला

इंदौर। लसूडिया क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी पर दो से ज्यादा बदमाशों ने हमला कर दिया। व्यापारी ने दिन में दुकान के बाहर हो रहे विवाद में बीच-बचाव किया था। आरोप है कि रात में घर लौटते समय रेलवे अंडरब्रिज के पास बदमाशों ने उसे घेरकर हमला कर दिया। घायल व्यापारी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लसूडिया थाना पुलिस के मुताबिक गौरी नगर निवासी शुभम यादव की शिकायत पर विनय और उसके साथियों के खिलाफ मारपीट और धारदार हथियार से हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। शुभम ने पुलिस को बताया कि उसकी सिंगापुर टाउनशिप में रेडिमेड कपड़ों की दुकान है।

चोरल-कालाकुंड

मार्ग पर क्षतिग्रस्त

रपटों का निर्माण शुरू

महु। चोरल-कालाकुंड मार्ग पर वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ी दो रपटों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। बरसात के दौरान इन रपटों की खराब स्थिति के कारण ग्रामीणों और पर्यटकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। निर्माण कार्य शुरू होने से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार, बारिश के मौसम में क्षतिग्रस्त रपटों के कारण मार्ग कई बार जोखिमभरा हो जाता था। इससे आसपास के गांवों के लोगों के साथ कालाकुंड आने वाले पर्यटकों को भी आवाजाही में दिक्कत होती थी। कुछ दिन पहले जिला कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त रपटों का निरीक्षण किया था। इसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर निर्माण कार्य को मंजूरी मिली और काम शुरू कर दिया गया।

नाना पटवारी के साथियों ने कबूला, चार पर केस दर्ज

20 से 100 रुपए मिलता है क्रिकेट सट्टे का कमीशन

इंदौर ● संवाददाता

एमडी ड्रम्स के मामले में आरोपी नाना पटवारी और उसके साथी सुमित मंत्री से बुधवार देर रात तक राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने पूछताछ की। इस दौरान पता चला कि नाना के साथी ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट ऑल पैनल पर क्रिकेट सट्टे के कमीशन एजेंट थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें प्रत्येक लेनदेन पर कमीशन मिलता था।

जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने नाना के चार साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल इस प्रकरण में नाना पटवारी का नाम आरोपी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। पुलिस के अनुसार जांच में संजय कौशल, मनीष जादौन, दिनेश उर्फ लल्ला चौहान, प्रीतेश त्रिपाठी सहित अन्य लोगों की भूमिका सामने आई है। इन पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे का नेटवर्क संचालित करने और बेटिंग आईडी उपलब्ध कराने का आरोप है। जांच में सामने आया कि कृष्णा नगर निवासी संजय कौशल ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट ऑल पैनल पर क्रिकेट सट्टे का कमीशन एजेंट था। प्रत्येक लेन देन पर उसे 20 से 100 रुपए तक कमीशन मिलता था। पूछताछ में संजय ने पुलिस को बताया कि सच्चिदानंद नगर (महु नाका) निवासी

मनीष पमनानी उसे ऑलपैन एक्स और ग्रेडेटेक्स डॉट कॉम की बेटिंग लिंक उपलब्ध कराता था। ये लिंक वॉट्सऐप के जरिए भेजी जाती थीं, जिन पर 5 हजार रुपए या उससे अधिक बैंलेस वाली बेटिंग आईडी मिल जाती थी।

डायरी में दर्ज था पूरा हिसाब

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि दिनेश उर्फ लल्ला चौहान, मनीष जादौन और प्रीतेश त्रिपाठी को ऑनलाइन बेटिंग ऐप की आईडी उपलब्ध कराई गई थी। इन आईडी और लेनदेन का पूरा हिसाब संजय कौशल एक डायरी में दर्ज करता था। अब पुलिस डायरी जब्त करने की तैयारी में है। डायरी में दर्ज नामों और लेनदेन के आधार पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।

आईटी एक्ट और सट्टा कानून के तहत केस

राजेंद्र नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ऑनलाइन जुआ, क्रिकेट सट्टा संचालन और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। जांच में यदि नाना पटवारी की संपत्तिता के ठोस साक्ष्य मिलते हैं तो उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कॉलेज के बाहर छात्राओं से अश्लील इशारे

इंदौर ● संवाददाता

देश के सबसे स्वच्छ और सुरक्षित शहरों में गिने जाने वाले इंदौर में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शहर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कॉलेज परिसर और आसपास बह रही असामाजिक गतिविधियों की शिकायत की तथा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई।

छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज के बाहर कुछ असामाजिक तत्व योजना उनका पीछा करते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं और अश्लील इशारों के जरिए उन्हें परेशान करते हैं। उन्होंने बताया कि कई युवक मोबाइल पर अश्लील फोटो और वीडियो दिखाते हैं तथा सार्वजनिक स्थानों पर अशोभनीय हरकतें करते हैं, जिससे छात्राओं में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा है। छात्राओं के अनुसार कॉलेज में करीब 10 हजार छात्राएं अध्ययनरत



हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। उनका कहना है कि पिछले तीन वर्षों से इस संबंध में कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई कुछ समय बाद धीमी पड़ जाती है और स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है।

इंदौर में मेडिकल छात्र और बुजुर्ग ने दी जान

इंदौर ● संवाददाता

इंदौर के निजी मेडिकल कॉलेज के एक छात्र और लसूडिया इलाके में रहने वाले एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों मामलों में पुलिस जांच कर रही है। खुदैल थाना पुलिस के मुताबिक निजी मेडिकल कॉलेज के थर्ड ईयर के छात्र रामगोपाल पाल (21) ने बुधवार दोपहर हॉस्टल परिसर में जहरीला पदार्थ खा लिया। कॉलेज प्रबंधन ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां रात में उनकी मौत हो गई। रामगोपाल बड़वाह के पास रामगढ़ के रहने वाले थे। पुलिस को उनके कमरे से कोई सुराहड नोट नहीं मिला है। तबीयत गंभीर होने के कारण उनके बयान भी दर्ज नहीं हो सके। पुलिस ने परिजनों

को सूचना दे दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मामले की जांच जारी है।

पेट की बीमारी से परेशान बुजुर्ग ने फांसी लगाई

लसूडिया थाना क्षेत्र के बापू गांधी नगर में रहने वाले राजेश जाधव (60) ने बुधवार शाम अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस के अनुसार, राजेश ने घटना से पहले पत्नी को ऊपर के कमरे में चाय लेकर आने के लिए कहा था। जब पत्नी चाय लेकर पहुंची तो वह फंदे पर लटके मिले। परिवार ने शुरुआती बयान में बताया है कि वह पिछले कुछ समय से पेट की बीमारी से परेशान थे। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक विवाहित बेटा हैं।

डॉक्टर के साथ ऑनलाइन ठगी, खरीदे 37 हजार के गिफ्ट वाउचर

इंदौर। विजयनगर थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर साइबर ठगी का शिकार हो गए। साइबर अपराधियों ने उनके क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग कर अमेजन से 37 हजार रुपए के गिफ्ट वाउचर खरीद लिए। मामले की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक निजी अस्पताल में कार्यरत डॉ. दीपक पाटीदार 7 जून को विजयनगर क्षेत्र में थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड का 37 हजार रुपए का बिल आया। जांच करने पर पता चला कि उनके कार्ड से अमेजन के गिफ्ट वाउचर खरीदे गए हैं। ठगी का पता चलते ही उन्होंने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नौकरी का झांसा देकर युवतियों को बंधक बनाने का आरोप

इंदौर। रतलाम की चार युवतियों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर से शिकायत कर आरोप लगाया है कि आयुर्वेदिक कंपनी में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन्हें राजेंद्र नगर क्षेत्र में बंधक बनाकर रखा गया। युवतियों का दावा है कि उन्हें जबर्न लड़कों के साथ हॉस्टल में रखा गया और अन्य लड़कियों को भी बुलाने का दबाव बनाया जा रहा था। किसी तरह वहां से भागकर वे रतलाम पहुंचीं और परिजनों को पूरी जानकारी दी। शिकायत मिलने पर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने मामले की जांच के निर्देश दिए। महिला थाना प्रभारी श्रद्धा यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम युवतियों को साथ लेकर राजेंद्र नगर क्षेत्र पहुंची। युवतियों की निशानदेही पर आनंद फार्म हाउस के पास स्थित एक मल्टी में दबिश दी गई।

सीसीटीवी कैमरे, पेट्रोलिंग और स्थायी सुरक्षा की मांग

छात्राओं ने प्रशासन से कॉलेज परिसर और आसपास नियमित पुलिस पेट्रोलिंग, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, महिला पुलिस की तैनाती तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त और स्थायी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त करना उनका अधिकार है और इसके लिए प्रशासन को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

कलेक्टर ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

मामले को लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि छात्राओं की शिकायत गंभीर है और इसे प्राथमिकता से लिया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक जांच कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश देने की बात कही।

15 साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट का फैसला, अटैच संपत्ति पर किसी ने नहीं किया दावा

ईडी केस में बरी, 2.19 करोड़ की संपत्ति राजसात

इंदौर ● संवाददाता

इंदौर में करीब 15 साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशेष कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी दंपती को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप से दोषमुक्त कर दिया, लेकिन ईडी की ओर से अटैच की गई करीब 2.19 करोड़ रुपए की संपत्ति पर किसी ने दावा नहीं किया। इसके चलते कोर्ट ने उस संपत्ति को शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिए हैं।

2011 में दर्ज हुआ था मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2011 में महु स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन क्लर्क राजेश नीम और अंजना नीम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इससे पहले राजेश नीम के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसी प्रकरण के आधार पर ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्रवाई शुरू की थी।



2.19 करोड़ की संपत्ति हुई राजसात

मामले की जांच के दौरान ईडी ने बैंक खातों के साथ इंदौर के इंद्रपुरी और महु स्थित एक प्लॉट समेत करीब 2.19 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अटैच की थी। सुनवाई के दौरान आरोपियों ने इन बैंक खातों और अटैच संपत्तियों पर अपना कोई दावा पेश नहीं किया। उनका कहना था कि यह संपत्ति उनकी नहीं है। इसके बाद विशेष कोर्ट ने 14 जुलाई को आदेश जारी कर पूरी अटैच संपत्ति शासन के पक्ष में राजसात करने के निर्देश दिए।

युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का लगाया आरोप

दूल्हे को शादी के मंडप से उठा ले गई इंदौर पुलिस

इंदौर ● संवाददाता

इंदौर के चंदन नगर थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में सीहोर निवासी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की टीम बुधवार को सीहोर पहुंची और शादी समारोह के दौरान मंडप से दूल्हे को हिरासत में लेकर इंदौर ले आई। मामले में युवती की शिकायत पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।

शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप

चंदन नगर थाना पुलिस के मुताबिक इलाके में रहने वाली एक युवती ने शिकायत दर्ज कराई है कि सीहोर निवासी रवि विश्वकर्मा ने शादी का वादा कर उससे प्रेम संबंध बनाए। इस दौरान करीब 1 साल तक उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से इनकार कर दिया। युवती ने बताया कि वह दो दिन से शिकायत लेकर थाने के चक्कर लगा रही थी। शिकायत मिलने के बाद महिला पुलिसकर्मियों ने आरोपी रवि विश्वकर्मा को फोन कर थाने बुलाया, लेकिन उसने आने से मना कर दिया।

शादी के मंडप से हिरासत में लिया

आरोपी के थाने नहीं आने पर चंदन नगर पुलिस की टीम बुधवार को सीहोर पहुंची। वहां रवि की शादी चल रही थी। पुलिस ने उसे शादी की रस्मों से पहले ही मंडप से हिरासत में



बहन के घर आने-जाने के दौरान हुई पहचान

पुलिस के अनुसार रवि विश्वकर्मा की बहन चंदन नगर क्षेत्र में रहती है। वह अक्सर अपनी बहन के घर आता-जाता था। इसी दौरान उसकी पहचान पड़ोस में रहने वाली युवती से हुई। दोनों के बीच प्रेम संबंध बने। युवती का आरोप है कि आरोपी ने शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया।

लिया और इंदौर लेकर आ गई। इसके बाद युवती की शिकायत पर उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया।

पहले समझौते का प्रयास, फिर एफआईआर

पुलिस ने बताया कि शुरुआती स्तर पर आरोपी को थाने बुलाकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराने और मामले का समाधान निकालने का प्रयास किया गया था। लेकिन आरोपी के थाने नहीं आने पर युवती की शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

संपादकीय

राम मंदिर दान लूट : कुतर्कों की इंतहेहा ?

प्रभु श्री राम मंदिर, अयोध्या में दान व चढ़ावे के पैसों व बहुमूल्य वस्तुओं की कथित लूट जैसे शर्मनाक कृत्य की चोतरफा निंदा की जा रही है। सुप्रसिद्ध कोर्ट में भी चंदा व चढ़ावा चोरी मामले में दायर एक याचिका पर सुनावई करते हुये केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है तथा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) को अब तक हूँ हूँ जांच की रिपोर्ट दायित्व का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस घटना को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और घोर निंदनीय बताते हुये कहा है कि दानपात्र से हूँ चोरी ने पूरे हिंदू समाज और राम भक्तों की श्रद्धा और भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई है जिससे संघ परिवार भी पूरी तरह आहत है। संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि इस महाप्राप में शामिल हर एक दोगी को कोटरमत्त सजा मिलनी चाहिए और चंदे की पवित्रता से कोई समझौता नहीं हो सकता। प्रांश संघ आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि यह केवल एक सांप्रसिनक लालपगवाई नहीं बल्कि आस्था का मामला है।

परन्तु सुप्रीम कोर्ट व संघ की चिन्ताओं से इतर एक बर्ग ऐसा भी है जो इस बेहद अफ़सोसनाक मामले में भी राजनीति का ऐसा लेख चढ़ाने की कोशिश कर रहा है जिससे विषय की गंभीरता को छिपाने की जगह जगहों और भक्तों का ध्यान दूसरी तरफ़ भटकना जा सके। उदाहरणार्थ राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे की कथित चोरी के मामले पर उभर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर सनातन धर्म, राम भक्तों की आस्था और अयोध्या की छविको नुक़सान पहुँचाने के लक्ष्य पर बदनाम करने का गंभीर आरोप लगाया है। योगी ने कहा कि विपक्ष एक छोटी सी घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारत की आस्था, अयोध्या की विरासत और प्रभु राम के नाम पर हमला करने का जैसे ठेका ले रखा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था, वे आज मंदिर के चंदे के नाम पर मचल रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियाँ चलावाई थीं, वे आज राम मंदिर की पवित्रता पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों की ग़लती की वजह से पूरे इस्लाम पर अयोध्या को कटघरे में खड़ा करना ग़लत है।

उपर स्वयं क हिंदू रक्षा दल क राष्ट्रीय अद्वैत बताने वाला गाजियाबाद क एक व्यक्ति जिसने एक सार्वजनिक लंगर के दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति हाथों से प्रसाद की थाली यह कक्कर छीन ली थी कि यह लंगर मुस्लिम आलों के लिये नहीं। इसी व्यक्ति ने अब राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे की चोरी के मामले पर बेहद विवादित और अजीबोगरीब बयान दिया है। उस ने इस मामले में आरोपियों का एक तरह से बचाव करते हुए कहा कि मंदिर हमारा है, चंदे हमारा है और अगर हमारे ही लोगों अर्थात हिंदुओं ने पैसा ले भी लिया है, तो विपक्ष या दूसरों को इससे क्या परेशानी है ? दूसरों को क्या मीचीं लग रही हैं ? इस ने तर्क दिया कि राम मंदिर में चंदा या दान देने वाले लोग भी भगवान राम में विश्वास रखते हैं और अज्ञान के कारण तो यह पैसा भिजाना है, वे भी भगवान राम के ही भक्त हैं। उसने कहा कि भगवान राम के आशीर्वाद से ही दान का कुछ पैसा उन आरोपियों के घरों तक पहुँचा है, इसलिए इस पर किसी को भी स्वावल ठठाने का कोई अधिकार नहीं है, हिंदुओं का पैसा तो हिंदुओं के पास ही रहा ? इसने उचित विरोधियों से ही स्वावल मूछा कि तुमने राम मंदिर में कितना चंदा दिया है ? उसके अनुसार जेहन्ने में मंदिर में एक रुपया भी दान नहीं दिया, उन्हें इस मुद्दे पर बोलोलेना या ठठालो ठठाने का कोई हक नहीं है, चंदा लूट व चोरी को जायज ठठालने वाली और भी कई बातें इस मूलतः राष्ट्रीय शर्रख ने कीं। इसी तरह अयोध्या के ही तपस्वी छलवनी के पीठाधीश जगन्नाथ परमहंस आचार्य ने इस मामले में आरोपियों की सजा को लेकर एक जातिगत और पक्षपातपूर्ण व विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि के मुख्य आरोपी टिटू यादव को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। जजकीट मामले में शामिल अन्य कतिपय उच्च जाति के अन्य आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, अविनारा शुक्ला, लवकुश मिश्रा व करुणेश पांडे का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि बाकी सबको छह-छह महीने की सजा देकर छोड़ देना चाहिए। उनके इस जातिगत दुर्धनवा पूर्ण बयान की भी भारी आलोचना हुई कि वे आस्था की इस बड़ी लूट में शामिल विशेष जाति के आरोपियों को केवल छह महीने की मामूली सजा देकर अपरा दफ्त करना चाहते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े कुछ कट्टरपंथियों और समर्थकों द्वारा इस विमर्श को बढ़ावा दिया जा रहा है कि हम (हिन्दू) सभ्यता में निपट लेंगे ।

संपादकीय

इंदौर, शुक्रवार, 17 जुलाई 2026

05

महंगाई की नई मार : आरबीआई के लक्ष्य से ऊपर पहुंची खुदरा महंगाई



देश में महागाई
ने एक बार फिर
आम लोगों की
चिंता बढ़ा दी है।
जून महिने में
खुरा महागाई
दर बढ़कर 4.38
प्रतिशत पर पहुँच
गई है। पिछले
17 महिनों में यह
पहला अवसर
है जब महागाई
भारतीय रिजर्व
बैंक आरबीआई
के 4 प्रतिशत के
निर्धारित लक्ष्य
से ऊपर पहुँची है।
इससे पहले मई
में खुरा महागाई
3.95 प्रतिशत
दर्ज की गई थी।
महागाई में यह
बढ़ोतरी मुख्य
रूप से खाद्य
वस्तुओं और
पेट्रोल-डीजल
की कीमतों में
लगातार हुई वृद्धि
का परिणाम मानी
जा रही है।

लेखक- कांतिलाल मांडोत

इसके साथ ही परिवहन लागत बढ़ने से रोजगार की जरूरत का लगभग हर सामान महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर दिखाई देने लगा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुन महीने में खाद्य महंगाई बढ़कर 5.32 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि मई में यह 4.78 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 5.45 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 5.09 प्रतिशत दर्ज की गई। यह स्पष्ट संकेत है कि गण और शहर दोनों ही महंगाई का मी झेल रहे हैं। फल, सब्जियां, दालें, खाद्य तेल, दूध तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने रसोई का खर्च काफी बढ़ा दिया है। मध्यम वर्ग और निम्न आवग के परिवारों के लिए घर का बजट संभालना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो गया है।

महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हुई वृद्धि भी रही है। ईंधन महंगा होने से माल ढुलाई का लागत बढ़ गई है। ट्रॉसपोर्ट महंगा होने का असर केवल परिवहन क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव हर उस वस्तु पर पड़ता है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है। किराना, फल-सब्जियाँ, दवाइयाँ, कपड़े, निर्माण सामग्री और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों भी परिवहन खर्च बढ़ने के कारण ऊपर चली जाती हैं। जून महीने में माल ढुलाई से जुड़ी सेवाओं की महंगाई दर बढ़कर लगभग 7.70 प्रतिशत तक पहुँच गई, जो यह बताती है कि परिवहन लागत अब महंगाई का बड़ा कारण बन चुकी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तेल और वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ाव बनानी होगी। अनिश्चितता ने भी ईंधन की कीमतों पर दबाव बनाया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव भारत जैसे आयात पर निर्भर देश पर पड़ता है। भारत अपने जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में वैश्विक परिस्थितियाँ किंगडूने पर घरेलू बाजार में भी पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं। यही

कारण है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का असर अब सीधे आम नागरिक की जेब पर महसूस किया जा रहा है।

महंगाई बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के लिए नया आधार वर्ष और नई उपभोक्ता टोकरी लागू होने के बाद यह महंगाई सूचकांक का अब तक का सबसे ऊंचा स्तर माना जा रहा है। नई उपभोक्ता टोकरी में लोगों की वर्तमान जीवनशैली और खर्च के पैटर्न को अधिक वास्तविक रूप से शामिल किया गया है। इससे महंगाई का आकलन पहले की तुलना में अधिक सटीक माना जा रहा है। हालांकि इससे यह भी स्पष्ट हुआ है कि लोगों के दैनिक खर्च में वास्तविक बढ़ोतरी पहले के अनुमान से अधिक है।

महाई का सबसे अधिक असर निश्चित आय वाले परिवारों पर पड़ता है। जिन लोगों की आय सीमित है या कीमतों का अधिक निर्यात वृद्धि नहीं होती, उनके लिए बहती कीमतों के बीच खर्च का स्तुन बनना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वेतनभोगी कर्मचारी, छोटे व्यापारी, किसान, मजदूर और पेंशनभोगी सभी इस स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं पर अधिक खर्च होने के कारण लोग अन्य जरूरतों पर खर्च कम करने को मजबूर हो रहे हैं। इससे उपभोक्ता मांग पर भी असर पड़ सकता है, जो अर्थव्यवस्था की गति को प्रभावित करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक का प्रमुख उद्देश्य महंगाई को नियंत्रित रखते हुए आर्थिक विकास को संतुलित बनाए रखना है। आरबीआई ने खुदरा महंगाई के लिए 4 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया है और 2 से 6 प्रतिशत के दायरे को स्वीकार्य सीमा माना गया है। हालांकि जून में महंगाई लक्ष्य से ऊपर पहुंच गई है, लेकिन यह अभी भी आरबीआई की निर्धारित ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत से नीचे है। इसके बावजूद लगातार बढ़ती महंगाई केंद्रीय बैंक के लिए चिंता का विषय बन रहता है। यदि आने वाले महीनों में महंगाई का दबाव बना रहता है तो ब्याज दरों को लेकर आरबीआई को अधिक सतर्क रख अपनाना पड़ सकता है।

बाजार विशषज्ञों का कहना है कि यदि खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण नहीं पाया गया और कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहें तो आने वाले महीनों में महंगाई

और बढ़ सकती है। दूसरी ओर यदि मानसून सामान्य रहता है, कृषि उत्पादन अच्छा होता है और सरकार समय रहते आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के कदम उठाती है तो खाद्य महंगाई में कुछ राहत मिल सकती है। अच्छी फसल से सन्धिज्यों, अनाज और दालों की कीमतों में स्थिरता आने की संभावना रहती है।

समकार के सामने फिलहाल दोहरी चुनौती है। एक ओर उभरे महंगाई पर नियंत्रण रखना है तो दूसरी ओर आर्थिक विकास की गति भी बनाए रखनी है। इसके लिए खाद्य आपूर्ति को मजबूत करना, जमाखोरी पर सख्ती, परिवहन व्यवस्था को सुचारु रखना और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होगा। यदि आपूर्ति श्रृंखला मजबूत रहती है तो कीमतों पर नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है।

आर्थिक जानकारी का मानना है कि महीना केवल आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध आम नागरिक के जीवन स्तर से है। जब खाद्य पदार्थ, ईंधन और दैनिक उपयोग के वस्तुएं महंगी होती हैं तो परिवारों की बचत कम होने लगती है। उपभोक्ता खर्च घटता है और इसका प्रभाव पूरे आर्थिक तंत्र पर दिखाई देता है। इसलिए महंगाई पर नियंत्रण केवल सरकार या आरबीआई की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उत्पादन, आपूर्ति और बाजार व्यवस्था के बेहतर समन्वय से ही संभव है।

जैन महीन के महेगाई के आकड़े यह संकेत देत है कि देश की अर्थव्यवस्था फिलहाल नई चुनौती का सामना कर रही है। फिस्ले 17 महीनों में पहली बार आरबीआई का लक्ष्य टूटना यह बताता है कि कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। यदि आने वाले महीनों में खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो आम आदमी की मुश्किलें बढ़ सक सकती हैं। ऐसे समय में सरकार, रिजर्व बैंक और संबंधित एजेंसियों को समन्वित प्रयास करते हुए महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण के उपाय करने होंगे, ताकि आम नागरिक को राहत मिल सके और अर्थव्यवस्था संतुलित विकास की दिशा में आगे बढ़ती रहे।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

बिहार में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए जारी नए ड्राफ्ट ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हमारे यहां शिक्षा नीति अक्सर विश्वविद्यालयों में नहीं, सचिवालयों की फाइलों में तैयार होती है। परिणाम यह हुआ कि जिस मसौदे को सरकार प्रदर्शित और गुणवत्ता का दस्तावेज बता रही है, उसे पीएचडी शोधार्थी अपने वर्षों के परिश्रम का अवमूल्यन मान रहे हैं। विरोध इतना तीव्र है कि विश्वविद्यालयों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल गूंज रहा है—क्या बिहार शोध संस्कृति को समाप्त कर प्रतियोगी परीक्षा संस्कृति को विश्वविद्यालयों पर थोपना चाहता है?

लेखक - कुमार कृष्णन

द केवल नियुक्ति नियमों का नहीं है। यह संघर्ष है जिसमें एक ओर वर्षों का शोध, नालयों की धूल और अकादमिक साधना है, वर कुछ घंटों की लिखित परीक्षा को योग्यता माना बनाने का आग्रह।

ना तर्क सीधा है। वह कहती है कि लिखित मान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और भाई-बहन तथा साक्षात्कार आधारित मनमानी समाप्त होकर पूरी तरह निराधार नहीं है। भारत के विद्यवालों में शिक्षक नियुक्तियों पर वर्षों से जातीय समीकरण, राजनीतिक प्रभाव और भ्रष्टाचार की अपारदर्शिता के आरोप लगते रहे हैं। न प्रणाली में सुधार की आवश्यकता से ही ई अहमत होगा।

विद्यार्थी सात वर्ष तक शोध करता है, और जेआरएफ जैसी कठिन परीक्षाएं उत्तीर्ण कर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करता है, सेमिनारों में भाग लेता है, पर नई समझ विकसित करता है, तो क्या अकादमिक यात्रा का मूल्यांकन तीन घंटे की परीक्षा से किया जा सकता है?

शालय और कर्मचारी चयन आयोग में होता है। विश्वविद्यालय केवल नौकरी-स्थिति नहीं है; वह ज्ञान निर्माण का केंद्र है। केवल पाठ्यक्रम पूरा नहीं करता, बल्कि प्रश्न पूछने की क्षमता, आलोचनात्मक दृष्टि और संस्कृति विकसित करता है। यदि शिक्षक की सीटी केवल प्रतियोगी परीक्षा बन जाएगी तो धीरे-धीरे कोविच संस्थानों की शाखा में प्रवेश पैदा होगा।

यह है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा
लगातार शोध, नवाचार और बहुविषयक
न देती है। केंद्र सरकार शोध को बढ़ावा देने

के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जैसी संस्थाओं की बात करती है। दूसरी ओर यदि राज्यों में पीएचडी की उपयोगिता ही कम होती दिखाई दे तो यह राष्ट्रीय लक्ष्य के विपरीत संकेत होगा।

बिहार का दुर्भाग्य यह भी रहा है कि वर्षों तक विश्वविद्यालयों में नियमित नियुक्तियाँ नहीं हुईं। हजारों पद रिक्त पड़े रहे। अनेक शोधार्थी अपनी युवावस्था का सबसे उत्पादक समय नियुक्ति की प्रतीक्षा में बिताते रहे। किसी ने तीस वर्ष की उम्र में पीएचडी शुरू की तो चालीस की उम्र तक भी उसे नियमित नौकरी नहीं मिली। ऐसे में यदि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भी नियमित ही बदल जाएं तो असंतोष स्वाभाविक है। यह केवल रोजगार का संकट नहीं, बल्कि नीति की विश्वसनीयता का संकट भी है।

आज भी अधिकांश विद्यार्थी शांभू इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि विश्वविद्यालय में अध्यापन का अवसर मिलेगा। यदि अंततः चयन का मुख्य आधार केवल लिखित तैयारी रह जाए तो युवा सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। ज्ञान प्रयोगशालाएँ और पुस्तकालय खाली होने लगेंगे। शांभू उपादान की जगह नोट्स और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संस्कृति विकसित होगी। यह किसी भी समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है।

इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि केवल पीपुर्चडी होने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ शिक्षक बन जाता है। भारत में शोध की गुणवत्ता पर भी गंभीर प्रश्न उठते रहे हैं। फर्ज शोध पत्रिकाएं, नकल, कॉपी-पेस्ट शोध प्रबंध और औपचारिक शोध संस्कृति जैसी समस्याएं वास्तविक हैं इसलिए गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है। लेकिन गुणवत्ता सुधारने का उपाय शोध को महत्वहीन बना देना नहीं हो सकता।

विश्व के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों पर दृष्टि डालें तो वहां सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति किसी एक परीक्षक से नहीं होती। उम्मीदवार के शोध, प्रकाशन, अध्यापन अनुभव, शोध प्रस्ताव, प्रस्तुतीकरण और विषय की गहराई का समग्र मूल्यांकन किया जाता है। क

विश्वविद्यालय डेमो लेक्चर कराते हैं ताकि यह देखा जा सके कि उम्मीदवार पढ़ा भी सकता है या नहीं। आखिर विश्वविद्यालय का शिक्षक केवल परीक्षार्थी नहीं, शिक्षक और शोधकर्ता दोनों होता है।

बिहार यदि वास्तव में उच्च शिक्षा में नई पहचान बनाना चाहता है तो उसे भी इसी संतुलित मॉडल की ओर बढ़ना होगा। लिखित परीक्षा हो, लेकिन उसके साथ शोध, शिक्षण अनुभव, पीएचडी, नेट, शोध प्रकाशन और अकादमिक उपलब्धियों को भी उचित महत्व मिले। केवल एक कसौटी से उत्कृष्ट शिक्षक नहीं चुने जा सकते।

सरकार के सामने यह भी चुनौती है कि वह पारदर्शिता और अकादमिक उत्कृष्टता के बीच संतुलन बनाए। यदि पूरी प्रक्रिया केवल साक्षात्कार आधारित होगी तो पक्षपात का आरोप लगेगा। यदि पूरी प्रक्रिया केवल लिखित परीक्षा आधारित होगी तो विश्वविद्यालय की प्रकृति बदल जाएगी। समाधान दोनों के बीच संतुलित व्यवस्था में है।

इस विवाद ने बिहार की उच्च शिक्षा की एक बड़ी विडंबना भी उजागर की है। एक ओर सरकार कॉलेज खोलने, विश्वविद्यालयों का विस्तार करने और हजारों नियुक्तियों की घोषणा करती है। दूसरी ओर शिक्षक चयन की प्रक्रिया ही विवादों में घिर जाती है। भवन बनाना आसान है, लेकिन विश्वविद्यालयों का बौद्धिक वातावरण बनाना कठिन है। उसके लिए उत्कृष्ट शिक्षक चाहिए और उत्कृष्ट शिक्षक केवल परीक्षा से नहीं चले जाते।

सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि इस पूरे मसौदे पर व्यापक शैक्षणिक विमर्श दिखाई नहीं देता। क्या विश्वविद्यालयों के कुलपति, विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ शिक्षक, शिक्षा विशेषज्ञ और शोधार्थियों से गंभीर संवादा हुआ? यदि नहीं, तो यह लोकतांत्रिक नीति निर्माण की कमजोरी है। शिक्षा पर निर्णय केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नहीं लिए जा सकते। परसों कि यह समझना होगा कि पीएचडी शोधार्थियों का विरोध

केवल नौकरी की मांग नहीं है। वे अपने शोध, अपनी अकादमिक पहचान और विश्वविद्यालयों की गरिमा के पक्ष में खड़े हैं। यदि हजारों शोधार्थी एक स्वर में कहें कि मैं कसौटी पर पुनर्विचार होना चाहिए, तो सरकार के लिए यह विचार नहीं बल्कि संवाद का अवसर होना चाहिए। बिहार लंबे समय तक नालंदा और विक्रमशिला जैसी विश्वविख्यात शिक्षण परंपराओं का प्रतीक रहा है। वहां शिक्षक की पहचान उसकी विद्वता से होती थी, न कि केवल परीक्षा में प्राप्त अंकों से। आधुनिक समय में भी यह ज्ञान आधारीत अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना चाहता है। तो उसे शोध और अध्यापन दोनों को समान सम्मान देना होगा।

शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल रिक्त पद भरना नहीं होता। उसका उद्देश्य ऐसे शिक्षक चुनना होता है जो आने वाली पीढ़ियों का बौद्धिक भविष्य तैयार करें। यदि चयन प्रणाली ही प्रतिभा को संदेह की दृष्टि से देखे और शोध को गौण बना दे, तो विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता धीरे-धीरे क्षीण होने लगेगी।

इसलिए बिहार सरकार को चाहिए कि वह इस मसौदे को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए। व्यापक विमर्श करे, सभी हितधारकों से सुझाव लें और ऐसा भीतर मॉडल तैयार करे जिसमें पारदर्शिता भी हो, मेट्रिड भी हो और शोध का सम्मान भी। क्योंकि विश्वविद्यालयों की सबसे बड़ी पूंजी उनकी इमारतें नहीं, उनके शिक्षक होते हैं। और शिक्षक चुनने में हुई एक भूल का असर कई पीढ़ियों तक दिखाई देता है। आज बिहार के सामने प्रश्न केवल यह नहीं है कि सहायक प्रोफेसर कैसे चुने जाए। असली प्रश्न यह है कि बिहार का ज्ञान का राज्य बना चाहता है या केवल परीक्षाओं का? यही प्रश्न इस पूरे विवाद का केंद्र है। और इसी का उत्तर राज्य की उच्च शिक्षा का भविष्य तय करेगा। सबसे गंभीर प्रश्न यह है कि क्या विश्वविद्यालयों में शिक्षक चुनने की प्रक्रिया और प्रशासनिक सेवाओं की भी शिक्षा एक जैसी हो सकती है? दोनों की प्रकृति, उद्देश्य और अपेक्षाएँ बिल्कुल अलग हैं।

न्यूज ब्रीफ

तिरुपति मंदिर में टूटा रिकार्ड... एक ही दिन में 97 करोड़ का दान

तिरुपति। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर को एक ही दिन में रिकार्ड तोड़ दान मिला है। नए संशोधित डोनेर पॉलिसी के लागू होने से ठीक पहले, नियमों में बदलाव और वीआईपी दर्शन की सुविधाएं कम होने की आहट के बीच, पुराने नियमों का फायदा उठाने के लिए देश-विदेश के श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से रिकार्ड तोड़ 96.98 करोड़ रुपए का भारी-भरकम दान दिया। दरअसल ट्रस्ट ने वीआईपी सुविधाओं और दर्शन नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जो मालवार आर्थी रात से लागू हुए। ट्रस्ट के अनुसार इसके पहले बुकिंग कराने वाले लोगों पर नए नियम लागू नहीं होंगे इसलिए लोगों ने उससे पहले ही पुराने नियमों के तहत दान की झड़ी लगा दी। संशोधित नीति के तहत अब स्लैब सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। अब दानदाताओं को उनकी प्रतीक दान राशि के आधार पर विशेष दर्शन दर्शन, सुपाथम प्रवेश, ब्रेक दर्शन, सुप्रभातम सेवा, कल्याणोत्सवम में भागीदारी, आवास की व्यवस्था और लड्डू, रेसमी वस्त्र, सोने-चांदी के सिक्के जैसे उपहार मिलेंगे। यह विशेषाधिकार 20 सौ और संस्थानों के लिए 15 वर्ष तक मान्य रहेंगे।

ममता को एक ओर झटका,
टीएमसी सांसद कोयल
मलिक ने दिया इस्तीफा

कोकलात। ममता बनर्जी की टीएमसी को झटका लगा है। अभिनेत्री से राजनेता बनीं पश्चिम बंगाल से टीएमसी की राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्वी से पद छोड़ने वाली वह चौथी सांसद हैं। कोयल से पहले भी 3 सांसद पद की सांसदों को को छोड़ चुके हैं। कोयल मलिक चार महीने पहले ही 6 अप्रैल को राज्यसभा सांसद बनी थीं। टीएमसी ने उन्हें पार्वी की सीट पर राज्यसभा के लिए चुना था। इसके बाद से उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा था। हालांकि चार महीने बाद ही उनके इस्तीफा देने से अंतरलोक का बाजार गर्ज हो गया और लोग इसके पीछे की वजह तलाश रहे हैं। हालांकि इनसे पहले 3 अन्य राज्यसभा सांसदों ने भी टीएमसी छोड़ दी थी और वे बीजेपी में शामिल हो गए। अब वे सभी राज्यसभा के उपचुनावों में उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। बता दें गुरुवार को टीएमसी नेता और एक्ट्रेस कोयल मलिक ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया।

श्रीकृष्ण पांच वक्त की नमाज पढ़ते थे वाले बयान पर बवाल

इटावा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच इटावा के मौलाना जरजिश अंसारी का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में मौलाना द्वारा भगवान श्रीकृष्ण को लेकर की गई टिप्पणियों पर हिंदू संगठनों ने कहा। आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो 23 जून का है, जिसमें मौलाना झारखंड में आयोजित एक धार्मिक सभा को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में वह कथित तौर पर दावा करते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण मुस्लिम थे और पांच वक्त की नमाज पढ़ते थे। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में श्रीमद्भगवद्गीता के एक श्लोक का उल्लेख करते हुए उसकी अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। हालांकि, धार्मिक विद्वानों का कहना है कि भगवद्गीता के जिस श्लोक का हवाला दिया गया है, उसमें हुस्लाम या नमाज का कोई उल्लेख नहीं है। उनका कहना है कि श्लोक का संबंध योग, आत्मसंयम और ईश्वर साधना से है, न कि किसी विशेष धार्मिक परंपरा से। वीडियो वायरल होने के बाद कई हिंदू संगठनों ने इसे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए मौलाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अयोध्या के कुछ संतों और धर्मगुरुओं ने भी इस बयान पर नाराजगी जताई और इसे ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत बताया।

जमीन, आसमान से लेकर समंदर तक...पुरी सुरक्षा घेरे में तब्दील

भगवान जगन्नाथ को यात्रा को लेकर 13,000 जवान और एनएसजी कमांडो तैनात

भुवनेश्वर ● एजेंसी

कड़ो सुरक्षा और भारी बाफ़िशा के अलर्ट के के बीच, भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्राजी और बहन सुभद्रा की सालाना रथ यात्रा के लिए पुरी में पूरी तरह तैयार कर ली गई है। लाखों श्रद्धालुओं की आनंद और मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट को देखते हुए, ओडिशा सरकार ने इस बार सुरक्षा और मैनेजमेंट को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। जमीन, आसमान से लेकर समुंद्र तक...पुरी को कई स्टॉपों वाले सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है। इस बार की सुरक्षा व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और बाफ़िशा के निपटने की रणनीतियां सबसे अहम हैं।

जानकारी के मुताबिक सालाना जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजामों पर, क्राइम ब्रांच के डिप्टी

इस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं कि एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। पूरे शहर में ट्रैफिक जंक्शन और भीड़ की आवाज़ों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी सर्विलांस सिस्टम लागू किया है, जिसमें सभी अहम और संवेदनशील इलाके शामिल हैं। एआईआईएनएलिसिस्ट और फेशियल रिकनिशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस सिस्टम को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद मिलती है, जिससे ट्रैफिक आसानी से चलता रहता है और भीड़ की निगरानी और नियंत्रण भी ठीक से हो पाता है... इस सिस्टम में मशीन लर्निंग शामिल है, जिसका मतलब है कि इस होने वाला डेटा और एआई एनालिटिक्स की क्षमताएं समय के साथ और मजबूत और अस्वरदा होती जायेंगी।

ध्यान देने वाली बात है कि रथ
उत्सव से ठीक पहले मंदिर वाले शहर



पुरी में जबरदस्त बारिश हुई। मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी-तूफान के लिए रेड वॉर्निंग जारी की है। ग्रैंड रोड से बारिश का पानी निकालने और जुलूस को आसानी से आगे बढ़ाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। भक्त 12वीं सदी के मंदिर से दूर श्री गुंडिचा मंदिर

तक रथ खींचते हैं। पुरी के कलेक्टर ने बताया कि पानी निकालने के लिए पंपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि भगवान बलभद्र का तालध्वज, देवी सुभद्रा का दर्पदलन और भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष - इन

रेप की कोशिश की परिभाषा
पर बवाल, महिला आयोग और
सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

पटना। देशभर में पटना और इलाहाबाद हाइकोर्ट की रेप की कोशिश से जुड़ी कुछ टिप्पणियाँ पर गहरा विवाद छड़ गया है। इन अदालतों ने अलग-अलग मामलों में कहा था कि महज महिला का सलवार उतारना या स्तन दबाना रेप की कोशिश नहीं। इन विवादित बयानों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडीब्ल्यू)

ने भी इस पर अपनी गंभीर चिन्ता व्यक्त की है। राष्ट्रीय महिला आयोगों की अध्यक्ष विजया राहाटकर ने स्पष्ट किया जयान आश्रमों की परिभाषा तय करते समय केवल शारीरिक शोषण को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि पीड़िता की गरिमा, उसके सहमति, घटना से उसके मन में पैदा हुआ भय और मानसिक पीड़ा को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। अन्ततः आयोग की अध्यक्ष राहाटकर ने चेतावनी दी कि यथार्थ न्यायिक प्रक्रिया कानून की तकनीकी परिभाषाओं तक सीमित रह जायेगी और पीड़िता के वास्तविक अनुभवों व कानून की मूल भावना को नजरअंदाज करेगी।

भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में नया इतिहास, स्काईरूट का विक्रम-1 18 जुलाई को भरेगा पहली ऑर्बिटल परीक्षण उड़ान



नई दिल्ली ● एजेंसी

भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 18 जुलाई 2026 का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी आर्कॉरूट एयरोस्पेस का पहला ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 18 जुलाई को सुबह 11:30 बजे ओडिशा प्रदेश स्थित तटीय धनव अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी-शार) के पहले लॉन्च पैड से अपनी पहली परीक्षण उड़ान भरने का प्रयास करेगा। यह पहली बार होगा जब निजी निजी भारतीय कंपनी द्वारा पूरी तरह डिजाइन और विकसित ऑर्बिटल श्रेणी का रॉकेट भारतीय धरती से लॉन्च किया जाएगा।

इस मिशन को 'मिशन आगमन' नाम दिया गया है। लॉन्च से पहले हवाई और समुद्री क्षेत्रों के लिए आवश्यक अधिसूचनाएं जारी कर दी गईं। और रॉकेट की उड़ान मार्ग तथा संभावित प्रभाव क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। स्काईरूप के सह-संस्थापक एवं सीईओ पवन कुमार चंदाना ने कहा कि विक्रम-१ के जमीनी स्तर पर सभी प्रमुख परीक्षण पूरे

पर लिए गए हैं। पहली परीक्षण ड्रान से प्राप्त आंकड़े भविष्य नियमित अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों के विकास की मजबूत नींव रखेंगे। विक्रम-1 अपने साथ कई तकनीकी प्रदर्शन पेलोड के अलावा 'कोस्मिक ब्लूम' नामक अल्ट्राकॉमिक और एक माइक्रो-अर्टीफिशियल बुद्धि प्रणाली के साथ भी अंतरिक्ष में ले जाएगा। कंपनी के अनुसार, लगभग सात अगिलेजा ऊंचाई वाला यह बहु-उपकरणों के संग्रह पूर्ण तरह कार्बन फाइबर प्रोजेक्ट संरचना से तैयार किया गया है। इसमें 3डी प्रिंटेड इंजन और उच्च क्षमता वाले ठोस रॉकेट गैजेट बूस्टर का उपयोग किया गया है। रॉकेट को 350 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। पहली परीक्षण ड्रान का लक्ष्य 450 किलोमीटर ऊंचाई पर 60 डिग्री झुकाव वाली कक्षा तक पहुंचना है। स्काईस्टार ससे परिलक्ष 18 नवंबर 2022 को विक्रम-एस का सफल परीक्षण प्रक्षेपण कर चुकी है। 'मिशन आगमन' भारत के अंतरिक्ष अंतरिक्ष उद्योग की वैश्वक मान्यता क्षेत्र में बड़ी छलांग का रास्ता रहा है।

बॉटम

संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस ने मानसून सत्र में सरकार को घेरने बनाया फुल-प्रूफ प्लान

नई दिल्ली • एजेंसी

सोनिया गांधी के आवास पर गुब्बारा को संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें मल्लिकार्जुन खडगे, शशि थरूर और जयराम रमेश को कहा नेता शामिल हुए। बैठक के बाद महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी ने अपनी बैठक प्रस्तावित विधेयों पर चर्चा की और तत्पश्चात् विपक्षी दलों के साथ मिलकर इनके आवाज उठाई जाएगी। संसद के मानसून सत्र में सरकार जिन प्रमुख विधेयों को लाने की तैयारी कर रही है, उनका पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने आगे कहा, मुझे ऐसे हैं, जिन्हें हम विशेष रूप से



जैसे चंदे की चोरी और विश्वासघात श्रीराम मंदिर के संबंध में रोज नए खुलासे हैं। हम अयोध्या में भाजपा और क्रस्सू गए घोटाले का मुद्दा जरूर उठाएंगे। नी

ई20 घाटाला जैसे कई मुद्दे भी हैं, जिसमें कई वरिष्ठ भाजपा नेता और उनके बेटे शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमें पता चला है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री

पारिसीमन विधेयक को वापस लाने का कानग्रेस का इरादा है। सरकार 17 अप्रैल को कानग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके बहुमत हासिल करने में सफल रही। विधेयक पर उसे बड़ा झटका लगा था। वह विधेयक को फिर से पेश करना चाहता था। कानग्रेस इस विधेयक का पहले भी विरोध कर चुका है और आगे भी करती रहेगी। साथ ही दलों की एकजुटता बनाए रखने की पूरी कोशिशें। जयप्रम रमेश ने कहा कि न्यायाधीश हटाने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के बौद्धिक में चर्चा हुई। इस विधेयक की पेशी के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) काई है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। कानग्रेस इस विधेयक का भी विरोध करेगी।

महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान
लागू करें, तो पूरा समर्थन देंगे

यजमान रमेश ने कहा कि हमने 16 और 17 अप्रैल को वर्तमान लोकसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण के संबंध में अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 में महिलाओं के लिए इस एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान शामिल है। यदि आप 543 सदस्यीय लोकसभा का एक तिहाई मान लें, तो यह 181 आता है। इसलिए, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान लागू करें, और हम अपना पूरा समर्थन देंगे। हालांकि, परिसीमा विधेयक जिसे महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में पेश किया गया था, वास्तव में महिला आरक्षण की आड़ में लाया गया एक खतरनाक परिसीमा विधेयक था।